Granting of B-2 Status to Pondicherry

802. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to grant B-2 status to the Union Territory of Pondicherry; and

(b) if so, by when the said proposal will be announced by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise in view of (a) above.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋण

803. श्री रणजीत सिंह :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री 28 अप्रैल, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 172 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में ओवर 17% आफ क्रेडिट डिसबर्सल्स ओवर ड्यू" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि का औसतन लगभग 17 प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों से बट्टे खाते डाला जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतिदेय अग्रिमों की धन-राशियां, बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई ऋण हानियों की राशियों की द्योतक नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, सभी वाणिज्यिक बैंक अशोध्य और संदिग्ध ऋण संबंधी अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार प्रावधान करते हैं और केवल वे ऋण ही बट्टे खाते डाले जाते हैं, जिन्हें वसूली योग्य नहीं समझा जाता है। वसूली के सभी सम्भव प्रयासों के पश्चात् ही बैंक अग्रिमों को बट्टे खाते डालते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भी, बट्टे खाते डाली गई ऋण हानियों के बारे में बैंक सूचना प्रकट नहीं करते हैं।

"दिल्ली में हवाला रैकेट"

804. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1992 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में ऐसे अनेक गुप्त ठिकाने हैं जहां से हवाला रैकेट चलाया जा रहा है जो मात्र संदेश के जरिए तस्करों के लिये विदेशी मुद्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गुप्त ठिकानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इस धंधे में मुद्रा-परिवर्तन को कमीशन सरकार को न मिलकर हवाला रैकेट चलाने वालों को मिलती है और इससे सरकार को राजस्व के रूप में मिलने वाली विदेशी मुद्रा की भारी हानि होती है;

(घ) यदि हां, तो उस धंधे से सरकार को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हो रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और हवाले के धंधे को शीघ्र बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) हवाला रैकेट गुप्त रूप से चलाया जाता है । अतः ठिकानों की संख्या अथवा सरकार को होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ङ) जब भी, इस प्रकार के अवैध सौदों का पता चलता है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 के अधीन, जिसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन और नजरबन्दी भी शामिल हैं, समुचित कार्रवाई की जाती है ।

Use of Solar Power in the Country

805. SHRI KRISHAN LAL SHARMA :

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that use of solar power is on the increase in the country ;

(b) if so, the details of the field in which solar power is being increasingly used at present and in which states of the country ; and

(c) whether in view of rising cost and inadequate supply of hydro electric power, Government propose to chalk out a plan to encourage its use in other areas also if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) Solar power is being increasingly used for lighting, water pumping, community lighting/television, communication, railways signalling electrification of small unelectrified villages/hamlets in almost all the States and Union Territories of the country, with the involvement of State nodal agencies, Electricity Boards, Govt. Departments and users.

(c) Taking into consideration the present cost of solar power systems, efforts are being made to encourage the use of such systems for small power applications in remote areas and for specialized applications such as communication, railway signalling etc. With further improvements in technology and cost reduction, use of solar power is expected to become more widespread.

Number of Villages Electrified in Tamil Nadu

806. SHRI R. T. GOPALAN : Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to refer the answer to Unstarred Question 899 given in the Rajya Sabha on the 3rd March, 1992 and state :

(a) what is the number of villages yet to be electrified in Tamil Nadu; and

(b) what is the number of villages proposed to be electrified during 1992-93, district-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI) : (a) As per available information, only 16 villages (1981 Census) are yet to be electrified as on 31-3-1991 in Tamil Nadu, of which only 7 villages are feasible for electrification.

(b) No target for electrification of villages has been fixed for 1992-93 in Tamil Nadu.

Recommendations made by Advisory Board on Energy

807. SHRI R. T. GOPALAN : Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) what are the details of the recommendations made by the Advisory Board on Energy for rural requirements of